

आज

बेबाक

लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाना पड़ा गया। इसके बावजूद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादात बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है। इसका मतलब साफ है कि लॉकडाउन का कड़ाई पूर्वक पालन कराने में शासन प्रशासन विफल रहे हैं। जिन कड़ी शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है उन शर्तों का भी उल्लंघन हो रहा है। यदि लॉकडाउन को लेकर यही धुलमुल रवैया रहा तो कोरोना के संग जीने की आदत डालने की तरह ही हमे लंबे समय तक लॉकडाउन भी झेलना पड़ा सकता है।

अच्छी खबर

कोरोना पर घिरा डब्ल्यूएचओ, जांची जाएगी भूमिका

एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तैवर के बाद कोरोना वायरस महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के भूमिका की अब जांच होगी। डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश इस वैश्विक संकट के प्रति संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र जांच पर मंगलवार को सहमत हो गए। डब्ल्यूएचओ की वार्षिक सभा में हिस्सा ले रहे देशों ने इस संकट के प्रति संयुक्त जवाबी कार्रवाई की अपील करते हुए आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया। यूरोपीय यूनियन द्वारा पेश प्रस्ताव में इस महामारी के प्रति अंतरराष्ट्रीय जवाबी कार्रवाई के निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समग्र मूल्यांकन की मांग की गई है। दुनियाभर में अबतक इस महामारी से 48 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 318,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

लॉकडाउन-4 के नियमों का पूरा पालन किया जाए

पूरी सावधानियां सुनिश्चित करें

फीवर क्लीनिक खोलने की तैयारी करें

नवप्रदेश संवादाता

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में लॉकडाउन-4 के नियमों का पूरा पालन किया जाए। सभी जिलों को इस संबंध में गाइड लाइन भिजवा दी गई है। लॉकडाउन-4 में दी गई

मुख्यमंत्री चौहान ने सभी जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की



छूटों के कारण लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे अतः अब सावधानियां और अधिक जरूरी है। लोगों की यह मानसिकता न बने कि कोरोना खत्म हो गया है। मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कहीं भी भीड़ न होने देना आदि सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना **शेष पृष्ठ 7 पर**

संक्रमण फैलाना आपराधिक लापरवाही

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन व्यक्तियों को हेम कार्टेडइन किया जाए वे नियमों का पालन करें। घर पर एकदम अलग रहे, किसी सदस्य से संपर्क न करें। पूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, वहीं तो पूरे परिवार के संक्रमित होने का डर रहता है। संक्रमण फैलाना आपराधिक लापरवाही है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि संक्रमित क्षेत्रों में लोग घर पर ही रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। जिन व्यक्तियों के सैमल लिए गए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से आईसोलेट किया जाए।

लोगों को जागरूक करें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे वे कोरोना के संकेत में सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। थोड़ी नी असावधानी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इस कार्य में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए।

अम्फान से अनर्थ का भय, आज तटीय इलाकों में देगा दस्तक



ओडिशा ने 11 लाख लोगों को निकालने की व्यवस्था की

पीके जेना ने कहा कि राज्य सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर 11 लाख लोगों को निकालने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 14 इकाइयां और ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल (ओडीआरएफ) की 20 टीमों को उन जिलों में तैनात किया गया है जिनके इससे प्रभावित होने की आशंका है।

ऐहतियान एनडीआरएफ ने की ये तैयारी

-एनडीआरएफ की 41 टीमों तैनात हैं जिसमें से सात रिजर्व हैं।
-15 टीम ओडिशा में काम शुरू कर चुकी हैं।
-19 टीमों वेस्ट बंगाल में काम कर रही हैं।
-ये टीमों छह जिलों में तैनात की गई हैं।
-एनडीआरएफ की कई टीमों स्टैंडबाई पर रखी गई हैं।
-ये टीमों बनारस, पुणे, चेन्नई और पटना में हैं।
-ये टीमों वहीं हैं जहां पर कि हवाई अड्डे हैं या फिर एयरपोर्ट्स के स्टेशन हैं।
-जरूरत पड़ेगी तो तुरंत एयरपोर्ट्स के विमान से टीमों को प्रभावित जगहों पर लाया जाएगा।

राहत के संकेत के बीच चिंता भी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि क्योंकि प्रचंड तूफान धीरे-धीरे कमजोर भी पड़ रहा है, ओडिशा पर इसका बहुत ज्यादा असर शायद न हो। हालांकि, पात्रा ने कहा कि ओडिशा के जगतसिंहपुर, कंदपाड़ा, भद्रक और बालासोर जैसे तटीय इलाकों में मंगलवार की शाम से बहुत तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो सकती है। विशेष बचाव आयुक्त पीके जेना ने कहा कि निचले इलाकों, तटीय जिलों में मिट्टी के घरों में रह रहे लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है और यह काम शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।

हमने फोनी से सीख ली है और ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है जब हम दोस्तों आपदा से गुज़ रहे हैं। हम लोगों को कोरोना वायरस के साथ-साथ इस गर्मकर आपदा से भी गुज़ना पड़ रहा है। हम लोग जितने भी राहत बचाव कर रहे हैं उन सभी में कोविड-19 की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं।

-एसएन प्रधान, एनडीआरएफ चीफ

एनडीआरएफ चीफ का कहना है

जम्मू-कश्मीर में विरोध के बीच लागू डोमिसाइल ऐक्ट, पाकिस्तान से भी इस ऐक्ट के खिलाफ विरोध के सुर

कम से कम 15 साल रहा है वह जम्मू-कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा

बीखलाए पाकिस्तान ने कहा- भारत ने कश्मीर में जो नया डोमिसाइल ऐक्ट लागू किया है वह पूरी तरह गैरकानूनी

श्रीनगर। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नया डोमिसाइल ऐक्ट लागू हो गया। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में संकशन 3ए जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य/यूटी के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी राज्य की विपक्षी पार्टियां तो इस ऐक्ट का विरोध कर ही रही हैं, अब पाकिस्तान से भी इस ऐक्ट के खिलाफ विरोध के सुर उभरने लगे हैं। नए डोमिसाइल नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में कम से कम 15 साल रहा है और 10वीं या 12वीं का एग्जाम यहां के किसी संस्थान से पास कर चुका है, तो वह जम्मू-कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा।

क्या है नया डोमिसाइल ऐक्ट?

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसेज) रूल्स 2020 को लागू कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र (पीआरसी) की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। इन सभी के लिए 15 वर्ष तक प्रदेश में रहने समेत अन्य श्रेणी की अनिवार्यता के नियम लागू होंगे।

बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल के नए नियमों को अधिसूचित किए जाने का स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि ये नए नियम सभी शरणार्थियों के साथ राज्य से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को भी उनके अधिकार दिलाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से सोमवार को जारी नए नियमों के तहत पश्चिम **शेष पृष्ठ 7 पर**

स्वच्छता सर्वे- 2020

सेवन स्टार रेटिंग में इंदौर को मिले 5 स्टार, भोपाल और उज्जैन को 3 स्टार मिले

नवप्रदेश संवादाता

इंदौर/भोपाल। तीन बार सफाई में नंबर वन का अवॉर्ड जीतने वाले इंदौर को इस बार 7 स्टार रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। इसके साथ ही इंदौर 5 स्टार पाने वाले टॉप -6 शहरों में शामिल हो गया है। मंगलवार दोपहर दिल्ली से जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का सिर्फ इंदौर ही इस लिस्ट में अपना स्थान बना पाया है। लॉकडाउन के बाद सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी होगी, इसमें इंदौर के पास चौका लगाने का अच्छा मौका है। वहीं, उज्जैन और प्रदेश की राजधानी भोपाल को थ्री रेटिंग मिली है। हालांकि, इंदौर ने इस बार सेवन स्टार रेटिंग लाने के लिए काफी मेहनत की थी। पिछले साल 5 स्टार रेटिंग में केवल 3 शहर ही अपना स्थान बना पाए थे। इस बार 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में **शेष पृष्ठ 7 पर**

तीखा प्रहार

ग्वालियर में गोडसे जयंती, कमलनाथ ने शिवराज को घेरा

नवप्रदेश संवादाता

ग्वालियर/भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जयंती पर हिंदू महासभा के कार्यालय में दीप जलाए गए। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कमलनाथ ने इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से स्पष्ट करने को कहा है कि वह बापू की सोच के साथ हैं या गोडसे की सोच के साथ। ग्वालियर के दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा के कार्यालय में गोडसे की मंगलवार को जयंती मनाई गई। कार्यालय में दीपक जलाए गए। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा है कि **शेष पृष्ठ 7 पर**

मुठभेड़

सुरक्षाबलों ने 12 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए

श्रीनगर। यहां डाउनटाउन इलाके में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने 2 आतंकीयों को मार गिराया है। सोमवार रात 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था। घनी आबादी वाले नवाकदल में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी छिपे थे, जिनमें से एक अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुरियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद भी था। जानकारी के मुताबिक, 29 साल का जुनैद अपने साथी तारिक अहमद शेख के साथ बीती रात यहां फंस गया था। पुलिस को टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी मौजूदगी को लेकर पुख्ता जानकारी मिली थी। रात 2 बजे पुलिस ने घेराबंदी कर सर्व ऑपरेशन चलाया था। एक घंटे बाद छिपे हुए आतंकीयों ने सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंका जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।



सियासत मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कांग्रेस को भाजपा मे दिख रही रार?

शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी कांग्रेस की रणनीति?

डॉ शिशिर उपाध्याय

भोपाल। कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव को लेकर एक दूसरे से दो-दो हाथ करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की चिंता सता रही है और दोनों ही पार्टियां अंदरखाने इसकी तैयारियां में भी करने लगी हैं। दरअसल, कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले 22 नेताओं को उनकी विधानसभा सीटों से टिकट दिया जाएगा लेकिन बताया जा रहा है कि

पार्टी के इस फैसले से स्थानीय नेता नाराज हो सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी समय रहते इन विवादों को सुलझा लेना चाहती है ताकि चुनावी मैदान में जाने से पहले किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तरफ बीजेपी उपचुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है तो वहीं कांग्रेस साइलेंट तरीके बैठकें कर रही है। साथ ही कांग्रेस के नेता मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नजर रखें हुए हैं। उन्होंने लग रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बीजेपी में जो लोग असंतोष होंगे वे खुलकर बाहर आएंगे और उसी का फायदा उठाना है।



सिंधिया पर सबकी नजर

दरअसल, उपचुनाव वाली अधिकांश सीटें ग्वालियर-चंबल संभाग की हैं। माना जाता है कि इन क्षेत्रों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का

ज्यादा प्रभाव है। यही कारण है कि दो दिन पहले बीजेपी की चुनावी बैठकों में सिंधिया को शामिल किया गया था। यही नहीं, सिंधिया लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है ताकि

बीजेपी को संगठन की चिंता

दरअसल, बीजेपी चुनावी तैयारियों से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, यही कारण है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारकों की नियुक्ति की जहां उपचुनाव होने हैं। इन सब के बीच पार्टी की असली चिंता उम्मीदवारों को लेकर है।

कांग्रेस कर रही इंतजार

यही कारण है कि कांग्रेस साइलेंट

असंतुष्टों पर नजर

यही कारण है कमलनाथ साइलेंट मोड में हर दिन बैठक कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस बैठक उनके विश्वस्त सहयोगी शामिल होते हैं। कांग्रेस बीजेपी के असंतुष्टों पर भी नजर रख रही है। उसे उम्मीद है कि उपचुनाव में सिंधिया समर्थक नेताओं को बीजेपी का टिकट मिलने से बीजेपी के स्थानीय नेताओं का असंतोष उसके लिए मददगार हो सकता है।

मोड में है और बीजेपी की हर चाल पर ध्यान रख रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी के कई नेता नाराज होंगे। इसके अलावे **शेष पृष्ठ 7 पर**

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस लेकर खास सफाई बतर्ता की हिनयत दी है। डॉक्टर मानिया वैन कोरसोव ने कस कि बच्चों में इपलामेनटी सिंड्रोम जैस हल्यो या पैरें पार लाल चकन निकलना, सूजन आना या पेट में दर्द होना कोरना के लक्षण हो सकत है। ऐस लक्षण दिखें तो अभिभावकों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल जे. रेयान का कहना है कि हो सकत है कि बच्चों में दिखने वाला मल्टीसिस्टम इपलामेनटी सिंड्रोम सीधे कोरना वायरस के लक्षण न होकर वायरस के खिलफुशरीर के येग प्रतिरोधक तंत्र की अत्यधिक सक्रियता का परिणाम हो। इसलिये अभी और जांच जरूरी है।

■ **न्यूज गैलरी**

91 ट्रेनं आई, 54 करोड़ खर्च, 16 हजार बसें लगीं फिर 47 हजार मजदूर पैदल एमपी बॉर्डर पहुंचे

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। लॉकडाउन के कारण मजदूरों का पलायन हो रहा है। कई राज्यों के मजदूर पैदल मध्यप्रदेश की सीमा पर पहुंच रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि दूसरे राज्यों के पैदल गए मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके राज्य की सीमा तक छोड़ा जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ मजदूरों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में श्रमिक पैदल आ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि अब तक विभिन्न प्रदेशों से 4 लाख 17 हजार मध्यप्रदेश में वापस आ चुके हैं। इनमें से 2 लाख 82 हजार सड़क मार्ग और एक लाख 15 हजार ट्रेन से आए हैं। केशरी ने बताया है कि अभी तक श्रमिकों को लेकर 91 ट्रेन मध्य प्रदेश आ चुकी हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश से एक, दिल्ली से एक, गोवा से दो, गुजरात से 25, हरियाणा से 13, कर्नाटक से दो, केरल से दो, महाराष्ट्र से 29, पंजाब से 3, तमिलनाडु से एक, तेलंगाना से 6 और तीन इंटरस्टेट ट्रेन आ चुकी हैं।

महाराष्ट्र से एमपी पहुंच रहे मजदूर

लॉकडाउन के मद्देनजर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने के इच्छुक श्रमिक बड़ी बिज्ञापन से मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 12 मई से अभी तक मध्यप्रदेश सरकार ने 1042 बसों के माध्यम से 46 हजार 890 श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक निःशुल्क भेजा है। भेजने के पूर्व इन सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए उन्हें भोजन-पानी भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। 18 मई को 223 बसों के माध्यम से 10 हजार से अधिक श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थल तक भेजा गया है। साथ ही श्रमिकों की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग कर रूट चार्ट अनुसार बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। सोमवार को 215 बसों के माध्यम से बिहार एवं उत्तर प्रदेश जाने वाले श्रमिकों को देवास भेजा गया है। जबकि मध्यप्रदेश के श्रमिकों को 8 बसों के माध्यम से विभिन्न जिला मुख्यालयों पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना संकट के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को मध्यप्रदेश वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्य में अभी तक लगभग 54 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक लाख 30 हजार प्रवासी श्रमिकों के खाते में 13 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जा चुके हैं। परिवहन के अतिरिक्त श्रमिकों के भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था में भी अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है। आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि श्रमिकों को लाने-ले जाने के लिये अभी तक 16 हजार 218 बसें लगायी गयीं हैं। इस पर 48 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे को ढूंढने वालों को देंगे इनाम, लापता होने के लगे पोस्टर

छिंदवाड़ा/भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ के गुमशुदा होने के पोस्टर शहर के कई इलाकों में लगाए गए हैं। यह पोस्ट किसने लगाए हैं यह अब तक पता नहीं चल पाया है। शहर में पोस्टर लगने से अब क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने भी पूछा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना काल में कितनी बार अपनी विधानसभा बुदनी गए और कितनी बार कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए। छिंदवाड़ा के कांग्रेस विधायक कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ की

प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 5241 पर पहुंची: ग्रीन जोन वाले जिलों में बाजार खुले

ग्रीन जोन में सुबह से सड़कों और बाजारों में भीड़ देखी जा रही है

इंदौर में सबसे ज्यादा 2637 और भोपाल में 1081 संक्रमित

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज-4 की तस्वीर साफ हो गई है। ग्रीन जोन में बाजार खुलने लगे हैं। सोमवार रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। कहा- रेड और ग्रीन जोन में जो सहूलियतें दी जा रही हैं। वे फिलहाल सिर्फ 7 दिन के लिए हैं। अगर हालात काबू में रहे तो रियायतें जारी रहेंगी। अगर संक्रमण बढ़ता है तो समीक्षा के बाद फिर सख्ती की जाएगी। मंगलवार दोपहर तक प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 5241 पर पहुंच गई। इंदौर में 2637 और भोपाल में 1081 मरीज हैं। कुल 252 की मौत हो चुकी है।

फ़ेज-4 में ऑरेंज जोन नहीं

राज्य सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बदलाव कर दिया। ऑरेंज जोन अब नहीं होगा। रेड जोन में इंदौर और उज्जैन का पूरा जिला रहेगा। भोपाल की सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन

गोविंदपुरा क्षेत्र में काम की अनुमति, 50 प्रतिशत कर्मचारियों से करा सकेंगे काम

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। लॉकडाउन पार्ट-4 में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के सभी कारखानों में काम चालू करने की अनुमति मिल गई है। शहर के छह कन्टेनमेंट क्षेत्र छोड़कर बाकी जगहों से 50 प्रतिशत कर्मचारी व मजदूर गोविंदपुरा क्षेत्र में काम करने आ सकेंगे। कारखानों में काम के दौरान उद्योगपतियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाकर काम कराना होगा। इसके अलावा मास्क व सैनिटाइज की व्यवस्था भी करनी होगी।

गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष



व मजदूरों को आने की अनुमति रहेगी। मंगलवार से कारखानों में काम शुरू कर रहे हैं। अधिकांश मजदूर पलायन कर चुके हैं। फिर काम कराने में चुनौतियां बहुत हैं। शासन की तरफ से अभी बिजली के बिल माफ, संपत्ति कर व बैंकों के ब्याज में छूट जैसी राहत नहीं दी है।



प्रभावी होगा। बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, देवास नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुशी के नगर पालिका एरिया को रेड जोन माना जाएगा। बाकी को ग्रीन जोन मानकर उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के हिसाब से गतिविधियां सामान्य की जाएंगी। रेड जोन में एक सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे। इसका क्राइसिस मैनेजमेंट रूप से चर्चा और समीक्षा के बाद उन्हें खोला जाएगा। मोहल्ले, एकल दुकानें, आवासीय इलाकों की दुकानें, बाजार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। रेड जोन के बाहर लाइसेंस वाली शराब और भांग की दुकानें खुल सकेंगी।

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम 7 से सुबह

हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचायेंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह की वीसी में कहा

मिशन मोड में कार्य कर 2023 तक लक्ष्य पूरा करेंगे

इस वर्ष 1280 करोड़ रुपए देगी केन्द्र सरकार

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा ली गई वीसी में कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। केन्द्र द्वारा लक्ष्य को वर्ष

2024 के स्थान पर वर्ष 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, तदनुसार योजना का पुनर्निर्धारण कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव तथा अन्य संबंधित उपस्थित थे। वीसी में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने



बताया कि जल-जीवन मिशन के अंतर्गत अब वर्ष 2023 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। इस वर्ष केन्द्र सरकार मिशन के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 1280 करोड़ रुपए का बजट देगी। इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाएगी। इसके साथ इस बार मध्यप्रदेश को लगभग 6500 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत प्रदाय किए जाएंगे। मनरेगा में 65 प्रतिशत राशि जल संबंधी कार्यों के लिए खर्च की जानी है अतः इसमें भी कुछ राशि का उपयोग जल जीवन मिशन के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में घर पर

नल के माध्यम से जल प्रदाय से शेष लगभग 85 प्रतिशत (103.67 लाख) परिवारों को एफएचटीसी (फंक्शनल हाऊसहोल्ड टैप कनेक्शन) के माध्यम से वर्ष 2023-24 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।

गत 9 माह में अपेक्षित प्रगति नहीं

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2012 में जल निगम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किए जाने के बाद लगभग 9

प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस विभाग ने राजपाल महोदय को लिखा पत्र

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में श्रम कानून एवं प्रावधानों में

श्रमिकों के साथ कुटाराघात कर, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य बनाए गए श्रम कानून एवं प्रावधानों में किए गए परिवर्तन को वापस ले मध्य प्रदेश सरकार

किए गए परिवर्तन को वापस लिए जाने एक आग्रह पत्र लिखा है। विषय में अपने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा को ढाल बनाकर उद्योगपतियों एवं कारखाना मालिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी सलाह पर श्रम कानूनों को श्रम संगठनों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बिना सलाह मशवरा किए परिवर्तित कर दिया है, जिसका राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों में अनावश्यक परिवर्तन कर मजदूर को सरकार से विमुख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के उद्योगों कल-कारखानों, बस, ट्रक, टैक्सी चालक, लोडिंग-अनलोडिंग वाहनों के चालक, पेट्रोल पंप मजदूर, मिल मजदूर सहित सभी कामगारों पर एवं मजदूरों पर परिवर्तन का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जहां एक और समूचा देश कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से जूझ रहा है, देश में लगभग एक लाख लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या 5 हजार के पार पहुंच गई है और लगभग 300 लोगों की अकाल मृत्यु होने से वे काल के गाल में समा गए हैं। लाखों मजदूर कोरोना महामारी के कारण सड़कों पर आ गए हैं, ऐसी भीषण गर्मी में 1500-2000 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उसे रास्ते में ना तो कोई सुविधा मिल रही है और ना ही घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई उचित व्यवस्था की जा रही है। बिसेन ने पत्र में आगे लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को 8 घंटे कार्य दिवस की कानूनी मान्यता दी गई है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा कानून कि धजियां उड़कर 12 घंटे कार्य कराये जाने का प्रावधान श्रमिकों के हितों के साथ बहुत बड़ा कुटाराघात है जो कि राज्य सरकार द्वारा थोपा गया प्रायोजित अत्याचार है। बिसेन ने कहा कि विवाद अधिनियम के तहत कामगारों की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 या उससे अधिक पर कानून परिवर्तन किया जाना

माह व्यतीत हो गए हैं परंतु प्रदेश में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। कार्य को गति देने के लिए प्रदेश में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन बनाया जाकर उसके अंतर्गत अपेक्ष समिति एवं एजीक्यूटिव समितियों का गठन कर लिया गया है।

लेन-देन के लिए सिंगल नोडल एकाउंट

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप मिशन के लेन-देन के लिए सिंगल नोडल एकाउंट खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही मिशन के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थाओं के एमप्लौमेंट की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूर्व से स्थापित तथा वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुल 321 गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध कराया दिया जाएगा। वर्ष 2020-21 की प्रस्तावित कार्ययोजना में अधिक से अधिक अजा-अजजा बाहुल्य गाँवों में कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे।

भाजपा नेता प्रेमचंद गुड्डू का बगावती बयान

...कहा- सिंधिया और सिलावट को चुनाव में हराना है; पार्टी ने नोटिस जारी किया

करीब 30 सालों तक कांग्रेस में रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया था

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल/ इंदौर। मध्यप्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो गई। विधानसनसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए



पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे तुलसी सिलावट के खिलाफ गुड्डू

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
E-mail- eewrknk@cgcgwrdd.in Phone No. & Fax No. 07868-222008
कार्यालयीन आदेश क्र. 171/व.ले.लि./2020 कांकेर, दिनांक 14/05/2020
// कार्यालयीन आदेश //
इस कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक 16/व.ले.लि./2019-20 सिस्टम क्रमांक 62081 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर जिले के विकासखण्ड कांकेर के अंतर्गत नाथियानवागांव एनीकट निर्माण कार्य की अनुमानित लागत राशि रुपए 28274000=00 के लिए आमंत्रित निविदा प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर के पत्र क्र. 4261707/निविदा प्रकोड2019/ रायपुर दिनांक 13.05.2020 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में उक्त आमंत्रित निविदा एकल होने के कारण निरस्त की जाती है।
जिसका जी नंबर 77857 दिनांक 12.03.2020 है।
कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कांकेर जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
जी-80817/9

मजेदार बात यह है कि इस पोस्टर के अंत में प्रकाशक में समस्त मतदाता छिंदवाड़ा विधानसभा और लोकसभा लिखा गया है।

कहां-कहां लगे पोस्टर

यह पोस्टर छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट, तहसील, पार्क के पास लगाए गए हैं। मंगलवार सुबह यह पोस्टर शहर में कई स्थानों पर देखे गए, तो यह मामला चर्चा का विषय बन गया। यह पोस्टर किसने लगाए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कई स्थानों पर घूम-घूम कर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर निकालते हुए भी नजर

आए। हालांकिपोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज कितनी बार गए बुदनी

कांग्रेस प्रवका नरेंद्र सलुजा ने ट्वीट कर कहा है कि जो भाजपाई कमलनाथजी व नकुल नाथजी को छिंदवाड़ा से लापता बता रहे है वो यह बता दें कि इस महामारी में शिवराज जी बुधनी कितनी बार गये ड कितने भाजपा के केंद्रीय मंत्री अपने इलाकों में गये ड अभी लॉकडाउन चल रहा है,सभी नियमो का पालन कर रहे है ।



तलाश वाले पोस्टर शहर में जगह-जगह लगा दिए गए हैं। पिता और पुत्र की फोटो लगे पोस्टर में लिखा गया है कि छिंदवाड़ा के लापता विधायक और सांसद को इस संकटकाल में छिंदवाड़ा की जनता

ढूंढ रही है जो इन्हें छिंदवाड़ा लेकर आएगा उसे 21 हजार रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इस पोस्टर में गाने की लाइन भी लिखी है- चिड़्डी न कोई सदेश, जाने वो कौन-सा देश जहां तुम चले गए।

...

राष्ट्रपति। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा प्रवासी मजदूरों के सम्बंध में की जा रही बयानबाजी को कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू बताया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और संचार विभाग के सदस्य सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह को मजदूरों की इतनी ही फिक्र होती तो वे कोरी बयानबाजी करने और बार्ड में जा कर पोटो खिंचवाने के बजाय इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से बात करके रमन सिंह मजदूरों के नाम पर केवल राजनीति करवाना चाह रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की समस्या अंतर्राज्यीय समस्या है। इनकी वापसी के बारे में केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनानी थी। दुर्भाग्य से केंद्र को भाजपा सरकार ने तीन महीने में ही मजदूरों की वापसी के लिये कोई नीति नहीं बनाया। मजदूर और अलग अलग राज्य प्रवासी मजदूरों को लेकर अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भौगोलिक रूप से 6 राज्यों से जुड़े होने के कारण राज्य से बड़ी संख्या में मजदूर प्रवेश गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और सामान्यसेवा संघान, तथा राज्य सरकार अक्सर मदद कर रही है। मैं भाजपा नेता कार्यकर्ता मदद को सामने नहीं आया।

छत्तीसगढ़ अठेला राज्य है जहाँ दूसरे राज्यों से पैदल चल कर छत्तीसगढ़ होकर अपने गृह राज्य जाने वाले मजदूरों के खाने पीने से लेकर सीमा तक जेडन की व्यवस्था की जा रही है।

मुंबई । बॉलीवुड अभिनेता और फिल्मकार संजय खान अपने बेटे जायद खान को रिलांच करने के लिये फिल्म बनाने जा रहे हैं। 'द सोर्स ऑफ़टीपू सुल्तान' जैसी कामयाब टीवी सीरीज बनाने वाले संजय खान एक बार फिर निदेशन में लौट रहे हैं। वह बेटे जायद खान को लेकर फिल्म का निर्माण-निदेशन करने वाले हैं, जिसकी कहानी भारत-पाकिस्तान के बीच हुए पहले युद्ध पर आधारित होगी। बताया जा रहा है कि संजय भारत-पाक युद्ध के वॉर हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पर फिल्म बना रहे हैं। संजय खान ने कहा, 'अ मैं स्क्रिप्ट पर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे जितना सम्भव हो सके, उतना विश्वसनीय बनाना चाहता हूँ। मैं भारतीय सेना की बहादुरी दिखाना चाहता हूँ कि पर्याप्त हथियार ना होते हुए भी वे किन्ती बहादुरी से लड़े थे। ब्रिगेडियर की कहानी साहस और उसूलों जैसे सिद्धांतों की दार्ष्टां है। अभिनेता ने कहा, 'जायद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम सितारों में से एक हैं। पिता होने के नाते, यह मेरा फर्ज है कि उसके लिए फिल्म बनाऊँ।'

मुखर्बी | बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेठ्ठी ने गोरे गोरे मुख गाना पर डांस किया जो वायरल हो गया है। शिल्पा लोक में रहने के बाद भी लगातार अपने वीडियो से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। शिल्पा अपने टिकटॉक वीडियो से खूब धमाल मचा रही हैं। उनके वीडियो इंस्टेंट पर छाए हुए हैं। हाल ही में शिल्पा एक वॉइसो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिल्पा 'गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा' गाना पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं। शिल्पा शेठ्ठी के इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वीडियो में शिल्पा शानदार डांस तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही अपने काले चश्मे के साथ स्टंट भी कर रही हैं। शिल्पा शेठ्ठी का यह टिकटॉक वीडियो खूब देखा जा रहा है। जल्द ही शिल्पा शेठ्ठी 'हंगामा 2' और 'निकम्मा' के जरिए एक बार फिर बड़े पैं पर नजर आने वाली हैं।

में उपलब्ध हैं और अनिवार्य कार्टीन का पालन करना है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय मैच अधिकारियों को अल्प अवधि के लिए नियुक्त किया जाए।

ये नियुक्तियाँ आईसीसी द्वारा स्थानीय एलीट और अंतर्राष्ट्रीय पैनल रेफरी और अम्पायरों में से की जाएँगी। जिस देश में कोई एलीट पैनल मैच अधिकारी नहीं होगा वहाँ स्थानीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पैनल मैच अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

■ न्यूज गैलरी

उपचुनाव से सरकार डर रही है- पूर्व मंत्री पीसी शर्मा

भोपाल। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर सरकार डरी हुई है इसलिए कोरोना को रोकने की जगह कर्ज माफी में घोटाले की बात कर रही है जबकि कर्ज माफी की वजह से किसान मजबूत हुआ है कर्ज माफी की वजह से किसानों की बम्पर फसल आई है। वर्तमान सरकार, कमलनाथ सरकार में हुए किसानों की कर्ज माफी की कितनी ही जांच करा ले उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने यहां भी सवाल किया है कि क्या सरकार उन मंत्रियों के विभागों की भी जांच करेगी जो मंत्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शराब की दुकान खोलने पर आपत्ति जताते हुए शर्मा ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर भी खोले जाना चाहिए।

स्कूल फीस, बिजली- पानी बिल, और प्रापटी टैक्स माफ करें सरकार : पीसी शर्मा

भोपाल। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए तीन माह की स्कूल फीस, बिजली-पानी बिल, और प्रापटी टैक्स माफ करने की मांग की है शर्मा ने कहा कि केवल स्कूल की ट्यूशन फीस माफ करने से लोगों का पला नहीं होगा बल्कि उन्हें राहत देने के लिए टैक्स और लॉक डाउन वाले महीनों में आये भारी भरकम बिलों से भी राहत देनी होगी। शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के साथ खड़ी है।

पुलिस विभाग भी जनता के लिये इस कोरोना के संकट में वरदान साबित हो रहा है



बड़वानी। बड़वानी की आजक्स थाने की लोकप्रिय सब इंस्पेक्टर जी आशा बामनिया जी ने आज सुबह नए युगल जोड़ों को रोककर उन्हें माक्स पदान किया और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत में माक्स भी शामिल हो इस कि शिक्षा भी दी। कोरोना के इस संकट में आशा जी बहुत शानदार वर्क कर रहे और अपनि पुलिस विभाग की जिमेदारी भी निभा रहे है ऐसे पुलिस आफसर को जनता भी सेल्यूट करती है।

कमलनाथ को घेरने की तैयारी में शिवराज सरकार ?

मंत्री समूह की बैठक में निर्णय, किसान कर्जमाफी की भी होगी जांच

छिंदवाड़ा में 12 हजार करोड़ के विकास कार्यों की खुलेंगी फाइल

शिवम यादव

भोपाल। सत्ता में आते ही एमपी की सियासत में बदला लेने की राजनीति शुरू हो जाती है। कमलनाथ की सरकार भी शिवराज सरकार की फाइलें खोल रही थीं। टारगेट पर बीजेपी के बड़े नेता थे। सत्ता में वापसी के बाद शिवराज ने भी कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए फैसलों की जांच करना रही है। जांच मंत्रियों की समूह कर रही है। अब तक

किसान कर्ज माफी से लेकर छिंदवाड़ा तक की खुलेंगी फाइलें

एमपी में बदले की राजनीति शुरू, कमलनाथ सरकार की खुलेंगी फाइलें



मंत्रालय में मंत्री समूह की 2 बैठकें हो चुकी हैं। सोमवार को मंत्री समूह की बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले में छिंदवाड़ा में हुए 12 हजार करोड़ के कार्यों की फाइलें सरकार ने तलब की हैं। बैठक में गृह मंत्री

नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद थे। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान छिंदवाड़ा में कई विकास कार्यों की शुरुआत की थी।

किसान कर्ज माफी की भी होगी जांच

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान कर्ज माफी को लेकर भी तत्कालीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसानों की कर्ज माफी की जांच होगी। बैठक में पूर्व सीएम के हस्ताक्षर युक्त किसान कर्जमाफी के कोरे प्रमाण पत्र रखे हुए थे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान कर्ज माफी सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। किसान के खातों में पैसा नहीं पहुंचा ही नहीं है। कहीं भी किसानों का 2 लाख कर्ज माफ नहीं हुआ है, जो प्रमाण पत्र दिए हैं, वह फर्जी हैं। हम इसकी तह तक जाएंगे। 'चिट्ठी-चिट्ठी' में पहले दिग्विजय, फिर शिवराज भी कूटे, नीतीश के बाद उलझन में ममता!

हम जांच के लिए तैयार

वहीं, बीजेपी ने इन जांचों के जरिए सीधे पूर्व सीएम कमलनाथ को लपेटने की तैयारी में है। कांग्रेस ने कहा है कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। प्रदेश के किसानों को पता है कि उनका कर्जा माफ हुआ है। शिवराज सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए यह सब कुछ कर रही है।

कमलनाथ ने भी करवाई थी जांच

सत्ता में आने के बाद कमलनाथ की सरकार ने भी बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ जांच शुरू करवाई थी। नर्मदा किनारे पौधा रोपण कार्यक्रम को लेकर जांच शुरू करवाई थी, जिसके जरिए शिवराज सिंह चौहान को तत्कालीन सरकार ने टारगेट किया था। वहीं, ई टैंडर घोटाले में वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच चल रही थी। पेंशन घोटाले मामले में कैलाश विजयवर्गीय रडार पर थे। अब वहीं कार्रवाई बीजेपी ने शुरू की है।

कोविड-19 : बिजली बिलों में राहत की मांग को लेकर ई-धरना देंगे 10,000 उद्यमी

नव प्रदेश संवाददाता

इंदौर। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लागू लॉकडाउन ने विरोध के प्रदर्शन का तरीका भी बदल दिया है। लॉकडाउन अवधि में बिजली बिलों में राहत की मांग को लेकर मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के करीब 10,000 उद्यमी बृहस्पतिवार को ई-धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र के इंदौर स्थित संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश (एआईएमपी) ने इस ई-धरने का आह्वान किया है। एआईएमपी के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने मंगलवार को बताया, लॉकडाउन के कारण प्रदेश में करीब दो महीने से अधिकांश कल-कारखाने बंद हैं और औद्योगिक विद्युत उपभोग न के बराबर है। इसके बावजूद

सूबे की विद्युत वितरण कम्पनियां तानाशाही रवैया दिखाते हुए हमें निर्धारित शुल्क (फिक्स्ड चार्ज) और अन्य अनुचित शुल्कों के आधार पर मोटी रकम के बिजली बिल भेज रही हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 के संकट से लड़ते-लड़ते उद्योग जगत का सब्र भी जवाब देने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिये कि वह अन्य राज्य सरकारों की तर्ज पर मध्यप्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली बिलों में राहत दिलवायें। डफरिया ने कहा, हमारी मांग है कि लॉकडाउन अवधि के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने मंगलवार को बताया, लॉकडाउन के कारण प्रदेश में करीब दो महीने से अधिकांश कल-कारखाने बंद हैं और औद्योगिक विद्युत उपभोग न के बराबर है। इसके बावजूद

लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करीब डेढ़ टन मछली अवैध रूप से शहर पहुंची, नगर निगम और पुलिस टीम ने दो से तीन लाख की मछली जप्त कर नष्ट किया

नेताजी सुभाष मार्ग भोई मोहल्ला में मछली व्यापारी दो भाई करीब 2 से 3 लाख की मछली बेचने को लेकर आए थे



इंदौर/नवप्रदेश। नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग भोई मोहल्ला में सोमवार देर रात क्राइम बांच, नगर निगम और सदर बाजार पुलिस ने दबिश दी। यहां से टीम ने करीब डेढ़ टन मछली बरामद की, जिसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मछली अवैध रूप से बाहर से लाकर यहां बेचने के लिए रखी गई थी। मिली जानकारी अनुसार क्राइम बांच को सूचना मिली थी कि प्रतिबंध के बावजूद नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग भोई मोहल्ला में बड़ी मात्रा में मछली अवैध रूप से बेचने के लिए शहर में लाई गई है। इस पर क्राइम बांच ने

इसकी सूचना निगम अधिकारियों को देने के साथ ही पुलिस को भी बतलाई। इसके बाद तीनों ही टीमों रात में भाई मोहल्ला पहुंचीं। यहां पर बलाए स्थान से टीम को करीब डेढ़ क्विंटल मछली मिली। टीम ने दो मछली व्यापारी भाइयों से पकड़ा है। ये दोनों भाई हैं और यहां मछली का कारोबार करते हैं। उक्त कार्रवाई नगर निगम अपर आयुक्त रजनीश कसेरा के आदेश पर की गई। मछली को जल संसाधन मंत्री व सागर संभाग के प्रभारी श्री तुलसीराम सिलावट को पत्र लिखा है। चौधरी ने लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के पहले दिन 24 मास तक कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज सागर संभाग में नहीं था।

सागर संभाग में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिंताजनक: सुरेन्द्र चौधरी

कोरोना संक्रमण,टोटल लॉक डाउन को लेकर म.प्र.कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरी ने सागर संभाग के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट को लिखा पत्र

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का तीसरे चरण की समाप्ति के बाद भी सागर संभाग में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने मध्यप्रदेश शासन के जलसंसाधन मंत्री व सागर संभाग के प्रभारी श्री तुलसीराम सिलावट को पत्र लिखा है। चौधरी ने लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के पहले दिन 24 मास तक कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज सागर संभाग में नहीं था।

और आज की बात करें तो लॉक डाउन तीन की समाप्ति पर सागर में कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है जो बेहद चिन्तनीय हैं। यही नहीं प्रदेश का इंदौर देश का 7वां और भोपाल देश का 11वां हॉटस्पॉट बन चुका है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार को पार कर चुका है, वहीं 38 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। यह सारे आंकड़े बेहद चिंताजनक है जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से आज भी प्रदेश सहित सागर संभाग में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की आवश्यकता है। आज भी पीपीई किट से लेकर मास्क व अन्य सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में कोरोना वारियर्स के संक्रमित होने खतरा बना हुआ है। चौधरी ने कहा कि संभाग के निजी अस्पतालों में आम मरीजों को इलाज नहीं

उपलब्ध हो पा रहा है, वही कोरोना प्रभावितों से भी भारी भरकम बिल वसूली पर भी शिवराज सरकार का कोई निंत्रण नहीं है। टोटल लॉकडाउन के चलते सागर जिले सहित सागर संभाग अन्य जिलों में आमजनों को दूध-दवाई व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, वही शराब की पर्याप्त आपूर्ति सरकार द्वारा करा दी गई है जो शिवराज सरकार के असली चहरे को उजागर करता है। चौधरी ने कहा है कि अन्य प्रदेशों से सागर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में घर वापसी कर रहे मजदूर भाईयो को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न मार्ग व सीमाओं पर साधन के अभाव में हजारों गरीब-बेबस-लाचार मजदूर भूखे प्यासे, भीषण गर्मी में नंगे पैर, पैदल ही अपने घर की ओर जाने को मजबूर हैं। सरकार के सारे दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं।

भाजपा नेताओं की सत्ता लिप्सा से फैल रहा कोरोना : जीतू पटवारी

भाजपा ने आपदा को अवसर में बदला

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जिन किसानों के ऋण माफ किए हैं और जिन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है उन किसानों के खाते में ऋण माफ करने की बजाय मध्य प्रदेश सरकार उपार्जन के भुगतान का पैसा ऋण खाते में जमा करके किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। कमलनाथ सरकार एक चुनी हुई सरकार थी जिसे जनता ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर भंडेठ दिया था। कमलनाथ जी की सरकार ने तीन चरणों में इस कर्ज की माफी की

।पहले चरण में लगभग 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया दूसरे चरण में 4 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया और तीसरे चरण का कर्जा एक जून से समायोजित किया जाना था इसका फैसला सरकार की कैबिनेट ने लिया था। इस फैसले के विरुद्ध धोखे से पीछे के दरवाजे से आई सौदाबाज शिवराज सरकार अगर किसानों का गला घोटती है तो किसानों के हितों के लिए ना केवल कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी बल्कि अवैधानिक तरीके से किसानों के हितों पर डाका डालने की इस कुचेष्टा का वैधानिक प्रतिकार भी करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा ने अपने नेता के आदर्श मंत्र के अनुरूप कोरोना की शआपदा को भ्रष्टाचार के अवसर श् में बदल दिया है।



कशमकश के बीच शिवराज की राजनीतिक कुशलता दिखेगी मंत्रिमंडल पार्ट 0.2 में ?

राजकिशोर सोनी

भोपाल। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बागियों के मदद से कमलनाथ की कांग्रेस सरकार की सत्तापलट के बाद अब इसके साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी में साफ साफ दिखने लगे हैं। लेकिन इस राजनैतिक कशमकश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की राजनीतिक कुशलता मंत्रिमंडल पार्ट 0.2 में देखने को मिलेगी। हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं की अंदरूनी नाराजगी के चलते मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल 0.2 का विस्तार में देरी हो रही है। क्योंकि बदले राजनैतिक घटनाक्रम के चलते मध्यप्रदेश के कई दिग्गजों के मंत्री बनने की राह कठिन हो गई है। उदाहरण के तौर पर मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में भाजपा के दिग्गज नेता रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा जो भाजपा सरकार में मंत्री थे। अब इनको मंत्री बनाये जाने को लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि रायसेन जिले से अब कांग्रेस से भाजपा में आये डॉ प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना तय है। यही स्थिति उन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है जहां जहां सिंधिया समर्थक मंत्री बनाये जाना तय है।



बहीं जिन 24 विधानसभाओं में विधानसभा के उप चुनाव होने हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी का दामन सभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 निर्लावित विधायकों को टिकिट दिया जाना भी तय है। ऐसे में इन विधानसभाओं के भारतीय जनता पार्टी के उन दिग्गज नेताओं की अपने पोलिटिकल कैरियर पर राजनीतिक संकट नजर आ रहा है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिंदगी भर मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के टिकिट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उनमें से अधिकांश भाजपा नेता दबी जुबान से विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के जिस शीर्ष स्तर से शिवराज सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से कमिटमेंट हुआ है। उसके

चलते इन नेताओं का विरोध भारतीय जनता पार्टी कितना सहन कर पायेगी यह देखने वाली बात होगी। यदि हम रायसेन जिले की सांची विधानसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में डॉ गौरी शंकर शेजवार और मुदित शेजवार का एक छत्र वर्चस्व रहा है। इस बार मुदित शेजवार ने चुनाव भी लड़ा और वे डॉ प्रभुराम चौधरी से पराजित हुए थे। मध्यप्रदेश के बदले हुए राजनैतिक परिदृश्य में शिवराज को मंत्रिमंडल गठन में खासी मसकत करनी पड़ रही है। क्योंकि भाजपा के कई सैनिकिय नेता कांग्रेस से भाजपा में आये इन नए नबेले नेताओं को हजम नहीं कर पा रहे हैं।और अंदरूनी असंतोख पनप रहा है। इसी के चलते इन नेताओं के समर्थक अब अंदरूनी विरोध करते नजर आ रहे हैं। और हो सकता है आने वाले उप चुनावों में अपने नेताओं की हरी झंडी मिलते ही यह नेता खुलकर विरोध के स्वर मुखर कर दें।हालांकि मध्यप्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में आये निर्लावित विधायकों ने सबसे पहले उन भारतीय जनता पार्टी के उन क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया है जो वर्तमान में भाजपा के स्थापित नेताओं के विरोधी कहे जाते हैं।



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुछ नए पदाधिकारियों राष्ट्रीय कार्यसमिति में सम्मिलित किया गया

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। राष्ट्रीय अटल सेना के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्यप्रदेश के प्रभारी श्री सुनील तिवारी जी ने अवगत कराते हुए बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय अटल सेना का विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय स्तर लेकर नीचे बूथ स्तर तक लाया जाएगा राष्ट्रीय अटल सेना भारत के राष्ट्रीय प्रमुख आर के रुद्रा जी एवं कोर कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में सभी के विचारों से सहमत होकर सभी संगठन की नींव को रखने वाले



भोपाल (नवप्रदेश) । गृह , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा, म.प्र. लिकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए।

राष्ट्रीय अटल सेना के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक

पदाधिकारियों को पुनः एवं कुछ नये पदाधिकारियों को राष्ट्रीय कार्य समिति में सम्मिलित कर संगठन को एक नई दिशा प्रदान किया गया। सभी नव निर्वाचित सम्माननीय सदस्यों को मुख्य रूप से मध्यप्रदेश की टीम श्रीकांत आचार्य-प्रदेश अध्यक्ष,शैलेन्द्र जोशी-संगठन महामंत्री, प्रमोद शर्मा-उपाध्यक्ष, आशीष तिवारी-प्रदेश उपाध्यक्ष, गोपाल पाटीदार-कार्यालय

प्रभारी, शिवम यादव- प्रदेश मीडिया प्रभारी, हिम्मत सिंह परिहार-सदस्यता प्रभारी,प्रदीप सिंह परमार - प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, अनिश दुबे -जिलाध्यक्ष भोपाल ,सन्नी जावला-जिला महामंत्री,मोतीलाल पाटीदार-सोशल मीडिया प्रभारी,पुणेंद्र पाठक,राजेश परमार,आनंद पांडे,जितेंद्र रजक आदि पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

राष्ट्रीय कार्य समिति में सम्मिलित पदाधिकारी

आर के रुद्रा-राष्ट्रीय प्रमुख	कुष्णा पांडेय-राष्ट्रीय महासचिव	अंकुश कुष्णा शास्त्री-राष्ट्रीय प्रचारक
मेहताब खान गैट-राष्ट्रीय महामंत्री संगठन	बॉबी पांडेय-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	पूजा कुमोठ सिंह-राष्ट्रीय महासचिव महिलावाहिनी
पिंकी जोशी-राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व प्रमोटी महिलावाहिनी	प्रतापधर शर्मा-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रमोटी छात्रसंघ	मोहिली श्यामबुद्ध-राष्ट्रीय सचिव महिलावाहिनी
रूपेश कुमार-राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यस्थाय कार्यालय प्रमोटी	देव शुक्ला-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	सुमंगी सुबोध सिंह- राष्ट्रीय सचिव
अनुरोधर मिश्रा-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष	सुनील तिवारी-राष्ट्रीय सचिव व प्रमोटी गोयाम्पटेश	शिवान पांडेय-राष्ट्रीय प्रचारक व प्रमोटी युवा सेना
निधि प्रकाश अवगल-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रमोटी (एनसीआर)	यश वर्मा-राष्ट्रीय सचिव	श्रीधर पांडेय-राष्ट्रीय मीडिया प्रमोटी
सत्येंद्र नाथराय सिंह-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	राकेश सिंह(राटी)-राष्ट्रीय सचिव	इंजी0अभिषेक सिंह- राष्ट्रीय आईटी सेल (सोशल मीडिया)प्रमोटी
लालेश विपाटी-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रमोटी उत्तरप्रदेश	नरेश वर्मा-राष्ट्रीय सचिव	वासिंता गोयवाली-राष्ट्रीय सचिव महिलावाहिनी
प्रकाश केशरी-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रमोटी झारखंड	बिना देवी-राष्ट्रीय सचिव व प्रमोटी पूर्वोत्तर प्रान्त	रश्मि ठाकुर - राष्ट्रीय सचिव महिलावाहिनी